20/0

प्रेषक.

विम्मी सचदेवा रमन, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स/निदेशक, नागरिक सुरक्षा उत्तराखण्ड देहरादन।

गृह अनुभाग-5

देहरादूनः दिनांक /8 फरवरी, 2014

विषय:-वित्तीय वर्ष 2013-14 में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु अनुपूरक बजट एवं केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना में प्राविधानित धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:—सीजी—90 / होगा / 2012 / 1125 एवं पत्र संख्या:—सीजी—90 / होगा / 2012 / 1126 दिनांक 25.01.2014 के अनुकम में निम्नांकित विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय कुल ₹ 2,65,70,000 / — (₹ दो करोड़ पैंसठ लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमित प्रदान करते हैं:—

अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—107—होमगार्ड्स—03—सामान्य अधिष्ठान—02—मजदूरी हेतु:—

कं0सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि	
1	02-मजदूरी	₹ 2,50,00,000 /-	
योग (₹	दो करोड़ पच्चास लाख मात्र)	₹ 2,50,00,000 /-	

अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—107—होमगार्ड्स—04—भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति वाला व्यय हेत:—

कं0सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	₹ 50,000 /-
2	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	₹ 1,00,000 /-
3	44-प्रशिक्षण व्यय	₹ 3,00,000 /-
	₹ 4,50,000 / –(₹ चार लाख	

अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवार्ये—00—आयोजनेत्तर—106—सिविल रक्षा—03—स्थापना(25 प्रतिशत केन्द्रांश)—01 हेत:—

कं0सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	₹ 10,000 / -
2	15–गाडियों का अनुरक्षण	₹ 10,000 /-

अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवार्ये—00—आयोजनेत्तर—106—सिविल रक्षा—01—केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—01—सिविल रक्षा हेत:—

स्वीकृत धनराशि
₹ 11,00,000 /-

- 2— यह आदेश वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या—284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30.03.2013 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है। कृपया उक्त शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 3— जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, साथ ही व्यय करते समय वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालन सुनिश्चित की जाय।
- 4— बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक / मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही अनुपूरक व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार / दायित्व सृजित किया जाय।
- 5— जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी०एम0—15 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 6— मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- 7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—107—होमगार्ड्स—03—सामान्य अधिष्ठान—02—मजदूरी, अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—107—होमगार्ड्स—04—भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति वाला व्यय, अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—106—सिविल रक्षा—03—स्थापना(25 प्रतिशत केन्द्रांश)—01, अनुदान संख्या—06 लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—106—सिविल रक्षा—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूरोनिधानित योजना—01—सिविल रक्षा के नामे डाला जायेगा।
- 9— अलोटमेंट आई०डी० S1402060196, S1402060195, S1402060194 तथा S1402060193 आवंटन पत्र दिनांक 17.02.2014 (पत्र के साथ संलग्न)।
- 10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः २०१ ८ ४४ ८११ (५) /13-19 दिनांक १८/३/१५ में प्राप्त उनकी सहमति व दी गयी शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीया, (विम्मी सचदेवा रमन) अपर सचिव। संख्याः— 128(1)/XX(05)/14—22(हो0गा0)/2013, तद्दिनांकित। प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून। 2—निदेशालय, कोषागार, लक्ष्मी रोड़ देहरादून।

3—वित्त अनुभाग—1 / 5 **4**—एन०आई०सी० सचिवालय परिसर।

5-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विम्मी सचदेवा रमन) अपर सचिव।